



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
Connecting. Empowering. Transforming.

**EXPORT PROMOTION COUNCIL
FOR HANDICRAFTS**

CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौता फ्रेमवर्क का स्वागत किया

भारत-अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट से द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा

नई दिल्ली/एनसीआर – 07 फरवरी 2026: हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट का स्वागत किया। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत और अमेरिका ने परस्पर एवं पारस्परिक लाभकारी व्यापार हेतु एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है, जिससे 13 फरवरी 2025 को प्रारंभ हुई व्यापक भारत-अमेरिका बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (बीटीए) वार्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता भी पुनः पुष्ट होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय यह फ्रेमवर्क, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित बाजार पहुंच बढ़ाने, सप्लाय चेन रेजिलिएंस मजबूत करने तथा आर्थिक सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कदम का स्वागत करते हुए **ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना** ने कहा, “अंतरिम समझौते का यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच अधिक संरचित और पूर्वानुमेय व्यापार सहभागिता की दिशा में एक ऐतिहासिक विकास है। हमारे हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से फ्रेमवर्क में उल्लिखित ‘होम डेकोर’ और ‘आर्टिसनल प्रोडक्ट्स’, यह टैरिफ, नॉन-टैरिफ बैरियर्स के समाधान और स्टैंडर्ड्स-सम्बंधित फैसिलिटेशन पर अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा, जिससे निर्यातक बेहतर योजना बना सकेंगे, खरीदारों को तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगे और दीर्घकालिक साझेदारियाँ विकसित कर सकेंगे।”

डॉ. खन्ना ने आगे कहा, “अमेरिका पारंपरिक रूप से हमारा सबसे बड़ा बाजार रहा है, जो कुल हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। ऐसे समय में जब टैरिफ से जुड़ी चिंताओं ने 50% तक के स्तर पर अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी, संयुक्त वक्तव्य अब संकेत देता है कि अमेरिका अपने ‘रिसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क’ के अंतर्गत भारत के मूल उत्पादों पर 18% की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा। आगे बढ़ते हुए, हम अपने सदस्यों के साथ मिलकर उत्पाद पोजिशनिंग को और मजबूत करेंगे, कम्प्लायंस तत्परता बढ़ाएंगे तथा बाजार आउटरीच का विस्तार करेंगे, ताकि ‘इंडिया हैंडमेड’ अमेरिका जैसे उच्च-मूल्य एवं गुणवत्ता-सचेत बाजार में निरंतर वृद्धि करता रहे।”

इसी भावना को दोहराते हुए **ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार** ने कहा, “यह फ्रेमवर्क इस बात को स्वीकार करता है कि प्रतिस्पर्धात्मकता केवल टैरिफ से नहीं, बल्कि नॉन-टैरिफ बैरियर्स, टेस्टिंग आवश्यकताओं, दस्तावेजीकरण और प्रक्रियागत पूर्वानुमेयता से भी तय होती है। यही वे क्षेत्र हैं जो अक्सर एमएसएमई के लिए वास्तविक लागत और जटिलता बढ़ाते हैं। संयुक्त वक्तव्य में नॉन-टैरिफ बैरियर्स, स्टैंडर्ड्स/कनफॉर्मिटी असेसमेंट और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर चर्चा एवं समाधान की प्रतिबद्धता से दिशा स्पष्ट रूप से कम घर्षण और अधिक मजबूत सप्लाय-चेन इंटीग्रेशन की ओर है। काउंसिल अब अंतरिम समझौते के अंतिम रूप लेने के दौरान उत्पाद-विशिष्ट प्रभावों को समझने हेतु हितधारकों के साथ निकटता से संवाद करेगी और मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि हस्तशिल्प क्षेत्र इस नए फ्रेमवर्क एवं आगामी (बीटीए) परिणामों का प्रभावी लाभ उठा सके।”

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष, श्री सागर मेहता ने कहा, “अमेरिकी बाजार गुणवत्ता में निरंतरता, समय पर डिलीवरी और विश्वसनीयता की मांग करता है। अंतरिम समझौते का पारस्परिक और संतुलित स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच आपसी विश्वास तथा साझा आर्थिक प्राथमिकताओं का एक सशक्त संकेत है। जैसे-जैसे व्यापार सहभागिता गहराएगी, निर्यातकों को वैल्यू चेन के स्तर पर पैकेजिंग एवं लेबलिंग अनुशासन, तेज प्रतिक्रिया चक्र, उत्पादन योजना तथा फुलफिलमेंट की तैयारी और मजबूत करनी होगी। बदलती खरीदार अपेक्षाओं के अनुरूप क्लेक्शंस को सौखिन्य करते हुए और व्यवसाय प्रक्रियाओं को उन्नत करके, ‘इंडिया हैंडमेड’ अमेरिका के बाजार में जिम्मेदारी के साथ स्केल कर सकेगा और उभरते अवसरों का लाभ उठा सकेगा।”

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने कहा, “हम अंतरिम समझौता फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने तथा व्यापक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (बीटीए) रोडमैप के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने हेतु भारत सरकार के सतत प्रयासों की सराहना करते हैं। जारी संयुक्त वक्तव्य नॉन-टैरिफ बैरियर्स के समाधान, स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेशन और स्पष्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन के माध्यम से व्यापार घर्षण कम करने पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से हस्तशिल्प एमएसएमई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईपीसीएच अब बाजार इंटेलिजेंस, बायर मोबिलाइजेशन, कम्प्लायंस सपोर्ट और क्षमता-वृद्धि पहलों के माध्यम से निर्यातक सक्षमकरण को तेज करेगा, ताकि यह फ्रेमवर्क अमेरिका के बाजार में वास्तविक परिणाम पूछताछ, रिपीट ऑर्डर्स और दीर्घकालिक साझेदारियों में परिवर्तित हो सके।”

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) देश से हस्तशिल्प निर्यात के संवर्धन हेतु एक नोडल संस्था है तथा देशभर के विभिन्न शिल्प क्लस्टरों में होम, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर और फैशन ज्वेलरी व एक्सेसरीज़ उत्पादों के निर्माण में संलग्न लाखों शिल्पकारों के “कुशल हस्तों के जादू” की ब्रांड छवि निर्मित करने हेतु कार्य करता है। श्री राजेश रावत, कार्यकारी निदेशक-ईपीसीएच ने बताया वित्त वर्ष 2024-25 में कुल हस्तशिल्प निर्यात ₹33,123 करोड़ (US\$ 3,918 मिलियन) रहा तथा अमेरिका को हस्तशिल्प निर्यात ₹12,814.73 करोड़ (US\$ 1,518.18 मिलियन) रहा।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:

श्री राजेश रावत, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच

+91-9810423612



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Connecting. Empowering. Transforming.

**EXPORT PROMOTION COUNCIL
FOR HANDICRAFTS**

CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ

PRESS RELEASE

EPCH Welcomes India-United States Trade Agreement Framework

India-US Joint Statement Reshapes Bilateral Trade

New Delhi/NCR – 07th February’2026 – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) has welcomed the India-United States Joint Statement issued by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, announcing, the United States and India have reached a framework for an Interim Agreement on reciprocal and mutually beneficial trade, reaffirming commitment to the broader U.S.–India Bilateral Trade Agreement (BTA) negotiations that was launched on 13 February 2025. The framework, agreed under the leadership Prime Minister Shri Narendra Modi, is a significant step towards expanding balanced market access, strengthening supply chain resilience, and deepening economic security alignment between India and the United States.

Welcoming the step, **Dr. Neeraj Khanna, Chairman, EPCH**, said, “The Interim Agreement framework is a landmark development towards a more structured and predictable trade engagement between the two countries. For our handicrafts sector, especially ‘home décor’ and ‘artisanal products’ specifically referenced in the framework will provide a greater clarity on tariffs, non-tariff barrier resolution and standards-related facilitation that can help exporters plan better, respond faster to buyers and build longer-term partnerships.

Dr Khanna further added that “the U.S. has traditionally been our largest market, contributing nearly 40% of total handicraft exports. At a time when tariff-related concerns had created uncertainty at levels as high as 50%, the Joint Statement now indicates that the U.S. will apply a reciprocal tariff rate of 18% on originating goods of India under its reciprocal tariff framework. Going forward, we will now work closely with our members to strengthen product positioning, enhance compliance readiness and expand market outreach so that ‘India Handmade’ continues to grow in a high-value, quality-conscious market like the USA.”

Echoing the similar sentiments, **Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor, EPCH and Chairman, IEML** shared that “the framework recognises that competitiveness is shaped not only by tariffs, but also by non-tariff barriers, testing requirements, documentation and procedural predictability, areas that often create the real cost for MSMEs. With the Joint Statement committing to address non-tariff barriers, standards/conformity assessment discussions and rules of origin, the direction is clearly towards reduced friction and stronger supply-chain integration. Now, council will engage closely with stakeholders to understand product-specific implications as the Interim Agreement is finalized and will work together to ensure that handicrafts sector can effectively leverage the new framework and upcoming BTA outcomes.”

Shri Sagar Mehta, Vice Chairman, EPCH, said that “the US market demands consistent quality, timely delivery and reliability. The reciprocal and balanced nature of the Interim Agreement sends a strong signal of mutual trust and shared economic priorities between India and the United States. As trade engagement deepens, exporters must respond with stronger readiness, packaging and labelling discipline, faster response cycles, production planning and fulfilment reliability. By aligning collections to evolving buyer expectations and upgrading business processes, India Handmade can scale responsibly and capture emerging opportunities in the US market.”

Shri Rajesh Rawat, Executive Director, EPCH, shared that “We appreciate the Government of India’s continuous efforts in advancing Interim Agreement framework and reaffirming commitment to the wider Bilateral

Trade Agreement (BTA) roadmap. The issued Joint Statement will focus on reducing trade friction through non-tariff barrier resolution, standards facilitation, and clearer rules of origin that can be particularly meaningful for handicraft MSMEs. EPCH will now accelerate exporter enablement through market intelligence, buyer mobilisation, compliance support and capacity-building initiatives so that this framework delivers practical outcomes in enquiries, repeat orders and long-term partnerships in the US market.”

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal institution for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) and the Handicrafts exports to USA during the year 2024-25 was 12,814.73 crores (US\$ 1,518.18 million) informed by Shri Rajesh Rawat, Executive Director-EPCH.

For more information please contact:

Shri Rajesh Rawat, Executive Director, EPCH
+91-9810423612

Encl: Hindi, English version